भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4531

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

भरतपुर को एनसीआर से बाहर किया जाना

4531. श्री भजन लाल जाटवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भरतपुर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से बाहर करने की लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए भरतपुर के निवासियों के लिए कोई विशेष राहत नीति लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार भरतपुर के विकास और इसे एनसीआर से बाहर करने की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): क्षेत्रीय योजना (आरपी) तैयार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) का अधिकार क्षेत्र राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-क्षेत्रों में आने वाले 55,083 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है।

भरतपुर के मामले में, एनसीआरपीबी ने पांच परियोजनाओं के लिए 161.72 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने 2024-25 में पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता (ऋण) के तहत 14 परियोजनाओं हेतु राजस्थान राज्य के लिए 288.33 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को अनुमोदित किया है, जिसमें भरतपुर जिले की 11 परियोजनाओं के लिए 225.22 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) शामिल है।

कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****